

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी ,
उत्तराखण्ड।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 20 सितम्बर 2010

विषय- शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति/नवीनीकरण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश संख्या डी-2046/सात-वि0म0-89 दिनांक 27 जुलाई, 1989 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)।

2- विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर- 7.08, 8.06 तथा 21.00 के प्राविधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन प्रस्तरों में यथा समय शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल में वृद्धि किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है परन्तु अधिवक्ताओं के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव समय से प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण प्रस्ताव भेजे जाने व अन्य किसी सम्बन्धित सूचना के अभाव के कारण नवीनीकरण के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर निर्णय लेने में विलम्ब होता है। कृपया विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.08, 8.06 तथा 21.00 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आती है कि शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए यथाशीघ्र प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3- शासन स्तर पर अपूर्ण सूचना, शिकायतों तथा अन्य किसी कारणों से अथवा किसी अन्य परिस्थिति वश निर्णय लेने में विलम्ब होता है तो ऐसे मामलों में जिनमें सम्बन्धित शासकीय अधिवक्ता (सिविल, फौजदारी व राजस्व) के कार्यकाल में वृद्धि के प्रस्ताव शासन को भेज दिए गये हैं परन्तु अपूर्ण सूचनायें, शिकायतों के निराकरण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका है तो उन मामलों में सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता के कार्यकाल में वृद्धि के स्पष्ट आदेश अथवा अन्यथा आदेश जब तक नहीं हो जाते तब तक उन्हें तदर्थ रूप से कार्यरत रहने दिया जाय। जिससे कि न्यायालयों का कार्य अनावश्यक रूप से बाधित न हो।

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं को उनके कार्यकाल की तिथि समाप्त होने के पश्चात तब तक कार्यरत रखा जाय जब तक कि शासन द्वारा उन्हें कार्यमुक्त करने के आदेश जारी न कर दिए जाय। यदि ऐसे किसी अधिवक्ता को कार्यमुक्त कराना आवश्यक हो तो शासन की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। शासकीय अधिवक्ताओं की 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर उन्हें कार्यमुक्त किए जाने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
प्रमुख सचिव।

संख्या-178(1)/xxxvi(1)/2010,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त जिला न्यायाधीश उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- विभागीय आदेश पुस्तिका/एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,



(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव।